शोध मंथन Vol. XVII No.1 Jan.- Mar. 2026 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *https://anubooks.com/journal-volume/shodhmanthan-vol-xvii-march-2026-no1*

नेपाल में जेन–जी आन्दोलन व राजनीतिक परिवर्तनः भारत–नेपाल संबंध पर प्रभाव

प्राप्तिः 01.03.26
स्वीकृतः 15.03.26

23

सचिन कुमार पाण्डेय
शोधार्थी, (राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश
ईमेलः isachinp27@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में श्रीलंका एवं बांग्लादेश की तरह सत्तारूढ़ सरकार के नीतियों, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठित जेन–जी वर्ग के द्वारा हिंसक एवं उग्र आंदोलन हुआ जिसके फलस्वरूप राजनीतिक परिवर्तन हुआ। इस शोध पत्र में नेपाल में जेन–जी वर्ग के संगठन द्वारा नेपाल में उग्र एवं हिंसक आंदोलन के परिणामस्वरूप नेपाल में प्रभाव के साथ नेपाल की आंतरिक राजनीति में जेन–जी समूहों में सत्ता संभालने को लेकर चुनौती की जांच की गई है। जिससे आगामी वर्षों में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टीयों के साथ संबंध किस प्रकार के होंगे का भी विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जेन–जी वर्ग के द्वारा उग्र एवं हिंसक प्रदर्शन की रणनीतियों का भारत के जेन–जी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा को भी रेखांकित किया गया है। इस शोध पत्र में नेपाल में जेन–जी वर्ग के द्वारा उग्र एवं हिंसक प्रदर्शन के विभिन्न कारणों एवं घटनाओं को रेखांकित करते हुए अंतरिम सरकार के गठन तक का विश्लेषण किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वैश्विक भू–पटल के मानचित्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भले ही दो अलग–अलग राष्ट्र (भारत व नेपाल) के रूप में नजर आते हैं लेकिन इन दोनों के मध्य भौगोलिक सीमांकन को अलग कर दिया जाए तो इन दोनों के मध्य विभाजन की रेखा खींचना कठिन होगा। भारत एवं नेपाल का संबंध वैदिक काल से घनिष्ठ रहा है। वर्तमान में आम बोलचाल की भाषा में भारत एवं नेपाल के बीच ''रोटी– बेटी'' शब्द का प्रचलन काफी ज्यादा देखा जाने लगा है। इसके पीछे कई मान्यताओं व प्रमाणाों जैसे– हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अयोध्या श्री राम एवं मिथिला नरेश जनक नंदनी सीता का विवाह से जोड़कर देखा जाता है।[1] भारत व नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की भौगोलिक सीमा मुख्यतः पांच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से सटी हुई

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.23

खुली सीमा रेखा है। जो दोनों देशों के मध्य लोगों को बिना वीजा के आवागमन के साथ व्यापार एवं रोजगार करने की सुविधा विद्यमान है। दोनों राज्यों के लोग एक–दूसरे की भाषा, संस्कृति एवं त्योहारों से काफी रू–ब–रू है। भारत एवं नेपाल में हिंदू जनसंख्या बहुल होने के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफी समानता दिखाई देती है।[2]

भारत और नेपाल में इतनी घनिष्ठता होने के बावजूद भी समय–समय पर अराजक तत्वों के कारण दोनों राज्यों में मतभेद पैदा करने की कोशिश समय–समय पर होती आ रही है जो नेपाली जनता एवं राजनीति के स्तर से आती रहती है इन मतभेदों के पीछे चीन की रणनीतिक प्रभाव को इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नेपाल बफर स्टेट होने के कारण इसकी उत्तरी सीमा चीन से लगती है जिससे दोनों बड़े राष्ट्रों के मध्य संतुलन बनाए रखना नेपाल के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा से विद्यमान रही है। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद नेपाल में विगत आंदोलन जेन–जी समूह द्वारा नेपाल के राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सरकार की नीतियों के विरूद्ध था। जिसके पीछे कई कारण विद्यमान है जो इस शोध–पत्र के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

नेपाल में जेन–जी आंदोलन व भारत–नेपाल संबंध

नेपाल में 8 सितंबर 2025 को नेपाली युवा सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। इसका मुख्य कारण नेपाल में इंटरनेट व मीडिय पर प्रतिबंध लगाने और व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध में था। यह बगावत जेन–जी के बैनर तले हजारों युवाओं ने राजधानी काठमांडू और विभिन्न शहरों में हिंसक प्रदर्शन किया। यहाँ जेन–जी से तात्पर्य जो व्यक्ति 1997 से 2012 के बीच जन्म लिया है। प्रदर्शनकारीयों में सैकड़ों छात्र स्कूल और कॉलेज के यूनिफार्म में देखे गए। हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारीयों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाही में 12 साल के स्कूली बच्चे सहित कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। जबकि अन्य 350 घायल हुए। इस दौरान काठमांडू में कर्फ्यू के साथ ही सेना तैनात कर दी गई। अन्य शहरों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर मौजुदा परिस्थिति पर विचार–विमर्श किया। बाद में नेपाल गठबंधन सरकार में गृह मंत्री एंव नेपाल कांग्रेस के नेता रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दियां नेपाल में हिंसा के मद्देनजर भारत में सीमा सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल ने सतर्कता बढ़ा दी। ओली सरकार ने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्रमा, युटुयूब, वाट्सएप, एक्स, लिंक्ड़इन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कार्ड, प्रिन्टरेस्ट, टेंसेन्ट, सिग्रल, थ्रेडस, वीचैट, क्कोंरा, टंबलर, क्लबहाउस, मैस्टोडान, रंबल, वीके, लाइन, आईएमओ, जैलो, सोल और हमरो पात्रो प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधित कर दिए थे और वाइबर, टिकटॉक, वी–टाक ओर नींबुज को पंजीकृत किया। यह कदम पंजीकरण नहीं करवाने को लेकर की गई थी। जिसकी तारीख 4 सितंबर तक रखी गई थी। नेपाल की कुल तीन करोड़ आबादी में 90 प्रतिशत लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, प्रतिबंध को तुरंत हटाने की मांग करते हुए 8 सितंबर को काठमांडू में हजारों युवा संसद भवन के सामने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारी झंडे और पोस्टर लिए हुए थे, जिन पर 'भ्रष्टाचार बंद करो, इंटरनेट मीडिया नहीं, इंटरनेट मीडिया पर से प्रतिबंध हटाओ और 'युवा भ्रष्टाचार के विरोधी' जैसे नारे लिखे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया

जब कुछ प्रदर्शनकारीयों बैरीकेडस तोड़कर संसद परिसर में घुस गये। एम्बुलेंस में आग लगा दी और संसद के सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज, आँसु गैस के गोले, हवाई फायरिंग और रबर की गोलीयों का इस्तेमाल किया। हिंसा के बाद संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे एक दिन पहले 7 सितंबर को काठमांडू के मध्य में स्थित मैतीधर मंडल में दर्जनों पत्रकारों ने भी सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया था। नेपाल कंप्यूटर एसोसिएशन (सीएएन) ने कहा कि फ़ेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों को एक साथ बंद करने से शिक्षा, व्यापार, संचार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही यह कदम नेपाल को डिजिटल रूप से पीछे ले जा सकते हैं। इस प्रतिबंध पर ओली ने कहा कि 'हम प्लेटफार्मों या इंटरनेट मीडिया के विरूद्ध नहीं है, बल्कि हम कानून व्यवस्था को नहीं मानने, अहंकार और हमारे देश की बेइज्जती करने के विरूद्ध है। एक वर्ष तक हमने इंटरनेट मीडिया कंपनियों से कहा कि नेपाल के कानून के तहत पंजीकरण करे टैक्स दे और जवाबदेह बने। लेकिन कंपनियों ने नियमों का पालन नहीं किया। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई नेपाल में कारोबार करे, पैसे कमाए और फिर भी कानून का पालन न करे।'' प्रदर्शनकारियों का कहना था सरकार भले ही कह रही है कि प्रतिबंध प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए लगाया गया है। लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है व सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। नेपाल में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि देशव्यापी जेन–जी आंदोलन में अराजक और प्रतिक्रियावादी तत्व शामिल हो गए थे। जेन–जी आंदोलन की मांगे भ्रष्टाचार की जांच प्रतिबंधित इंटरनेट मीडिया की बहाली थी लेकिन सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई। बाहरी तत्वों ने तोड़–फोड़ की ओर जबरन संसद भवन में घुसने की कोशिश की जिससे हिंसा भड़क गई। पूर्व डीआइजी हेमंत मल्ला ने कहा 'सरकार की खुफिया एजेंसी ने स्थिति का सही आकलन और तैयारी की होती तो वे स्थिति को और बेहतर ढंग से संभाल सकते थे।

नेपाल में बिगड़ते परिस्थिति का असर भारत पर भी पड़ा। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जिनके रिश्तेदार व परिचित नेपाल में रहते है। नेपाल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए प्रतिबंधों से इंटरनेट कालिंग की सेवा प्रभावित हुई। लोगों को सामान्य कालिंग से बातचीत करनी पड़ रही थी जिसका शुल्क 12 रुपये प्रति मिनट देना पड़ता है। नेपाल में इन प्रतिबंधों से भारतीय सीमा से सटे नेपाली क्षेत्रों में यहाँ के सिम कार्ड की मांग बढ़ गई। इसके अलावा नेपाल में हिंसात्मक प्रदर्शन व बिगड़ते परिस्थिति से पर्यटकों की संख्या में 70 प्रतिशत की कमी आई। जिसका प्रभाव नेपाल की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा।[3]

9 सितंबर को जेन–जी प्रदर्शनकारीयों द्वारा भड़का आंदोलन और उग्र हो गया। प्रदर्शनकारीयों ने संसद व सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति कार्यालय, पीएम आवास, मुख्य प्रशासनिक परिसर, सिंह दरबार व वरिष्ट नेताओं के घर में आग लगा दी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, वितमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल व कई अन्य नेताओं के घरों में घुसकर

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.23

पीटा। भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री झाला खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। राजनीतिक दलों, अखबारों व टीवी चैनलों के दफ्तरों में आगजनी के साथ कई बैंकों में लूटपाट की गई। बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इससे भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए और हिंसा जारी रखी। लिहाजा रात में सुरक्षा की कमान सेना ने अपने हाथों में ली। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने प्रदर्शनकारीयों से संयम बरतने व वार्ता के माध्यम से संकट के समाधान का आग्रह किया। सेना प्रमुख अशोक राज सिगड़ेल ने चेतावनी दी कि अगर हिंसक गतिविधियां जारी रही तो इसे रोकने के सभी उपाय किए जाएंगे। लोगों से आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया और कहा, कुछ समूह कठिन परिस्थितियों में अनुचित लाभ उठा रहे हे जिससे आम नागरिकों व सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँच रहे हैं। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए काठमांडु के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उड़ान की सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारीयों ने काठमांडू में 'केपी चोर, देश छोड़ और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करो' नोर भी लगाए। नेपाल में ओली सरकार के भ्रष्टाचार, उसकी अन्य लोगों के प्रति उदासीनता के साथ ही मंत्रीयों व अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों की फिजुलखर्ची वाली विलासतापूर्ण जीवनशैली को लेकर भी काफी गुस्सा रहा। प्रदर्शनकारीयों की मांगे थी कि ओली सरकार को हटाकर एक नई सरकार का गठन किया जाए। नेपाल के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गांरटी मिले तथा राजनीतिक पद संभालने वालों के लिए सेवानिवृति की आयु तय हो। प्रदर्शनकारीयों के बीच ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह (बालेन) का नाम भी सुर्खीयों में रहा। इसके अलावा जेन–जी के सबसे बड़े आंदोलन का मुख्य चेहरा 36 वर्षीय सुदन गुरुंग के रूप में आया। जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से रैलीयों का आव्हान किया था। नेपाल में जन विद्रोह से पूर्व केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा 16–17 सितंबर 2025 को पूर्व निर्धारित थी। जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अहम घोषणाएं भी होनी थी।[4] जेन–जी युवाओं के दो दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाल लिया। संपूर्ण नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिसके बाद नेपाल में हालात सामान्य होते गए। सेना की मध्यस्थता के बाद जेन–जी प्रदर्शनकारीयों और राजनीतिक दलों की बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनी। पाँच घंटों की बैठक के बाद नेपाल की पूर्व एवं प्रथम महिला न्यायाधीश सुशील कार्की को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सुशीला कार्की जिनकी शिक्षा 1975 में भारत के बीएचयू के राजनीति विज्ञान विभाग से ही हुई है। बनारस में ही उनको जीवनसाथी दुर्गा प्रसाद सूबेदी मिले था। नेपाली कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, सूबेदी 1970 के दशक में नेपाली कांग्रेस के युवा क्रांतिकारी सदस्य थे। वह उस समूह का हिस्सा थे जिसने नेपाल के इतिहास में पहली बार तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के शासनकाल के दौरान पार्टी विहीन पंचायत व्यवस्था को उखाड़ फेकने के लिए पार्टी की सशस्त्र क्रांति के लिए 30 लाख रुपये जुटाने हेतु रायल नेपाल एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया था।'' जुलाई, 2016 में नेपाल की 24वीं प्रधान न्यायाधीश (प्रथम महिला न्यायधीश) के रूप में 11 महीनों तक पद पर रहते हुए कई ऐतिहासिक निर्णयों को दी जिसके बाद चर्चा में आई। अपनी कार्यशैली से वजह से ये हमेशा कम्युनिष्ट शासन के निगाहों में खटकती रही। इसके अलावा बैठक में शामिल सदस्यों ने संसद भवन में नरसंहार का आरोप लगते हुए आदेश देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की गिरफ्तारी की मांग की। बैठक में जेन–जी को राजनीति में

लाने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख की व्यवस्था करने, पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी व कर्मचारीयों के दलगत संगठनों पर पुर्न प्रतिबंध की बात कही गयी। इसके अलावा जेन–जी की वर्चुअल बैठक में 7800 सदस्यों ने नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाने को लेकर भी प्रस्ताव पास किए गए। इसमें नेपाल की वर्तमान संसद भंग करना, दो महीने में नया संविधान तैयार करके छह माह में संसदीय चुनाव कराना प्रमुख है। इसके अलावा जेन–जी ने अपनी मांगों के अंतर्गत जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ 46 वर्षों से सार्वजनिक पदों पर बैठे सभी लोगों के संपत्ति जांच हो तथा संवैधानिक परिषदों में दलगत नियुक्तियाँ रद्द कर योग्यता के आधार पर करने की मांग की।

नेपाल में सरकार के विरूद्ध जेन–जी हिंसक आंदोलन का फायदा उठा कर देशभर के विभिन्न जेलों से 15000 से अधिक कैदी फरार हो गए। जिसके बाद भारत के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के सात सीमावर्ती जिलों हाई अलर्ट जारी किए जाने के बाद सक्रियता बढ़ा दी गई। जिनके भारत में घुसपैठ करने की आशंका थी। फिर भी कई कैदी नेपाल सीमा पर बहराइच, महराजगंज व अन्य स्थानों पर एक दर्जन से अधिक कैदी पकड़े गए। जो भारतीय मूल के थे। जिसके बाद भारत के गृह मंत्रालय के निर्देश पर जांच करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नेपाल में हालात सामान्य होने के बाद फंसे भारतीय लोगों को नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से भारत के निजी विमानन कंपनियों एयर इंडिया और इंडिगो से निकालना शुरू कर दिया।[5]

हालांकि सेना के साथ बैठक में अंतरिम सरकार के सहमति के बाद जेन–जी आंदोलन के विभिन्न समूहों में अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर गतिरोध पैदा हो गया। अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर 11 दिसंबर 2025 को जेन–जी के दो समूह आपस में भीड़ गए। इससे सेना मुख्यालय के सामने अफरातफरी मच गई। इसके बाद सेना ने मुख्यालय परिसर खाली करा लिया। इस पर युवाओं ने सेना के विरोध में नारेबाजी भी की। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व उनकी मंत्रीपरिषद के सदस्यों को नजरबंद कर दिया गया। 10 दिसंबर 2025 को नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन में पहले काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और जेन–जी के संयोजक सुदून गुरुंग का नाम चर्चा में आया था। लेकिन देर शाम पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी। जिससे बालेंद्र शाह के समर्थन में एक गुट ने कार्की का विरोध किया, पर शाह की कार्की के समर्थन में फेसबुक पोस्ट के बाद लगा गतिरोध खत्म होने वाला है। इसी बीच कुछ युवाओं ने मेयर हरक सांगपाँग का नाम उछाल दिया। 11 दिसंबर 2025 को सुबह में राष्ट्रपति पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगड़ेल के साथ सेना मुख्यालय में आयोजित बैहक में एक गुट ने कार्की की उम्र अधिक बताते हुए उनके नाम पर असहमति जता दी। कुछ और समूहों ने भी संविधान का हवाला दिया, जिसके तहत अवकाश प्राप्त न्यायधीश के नियुक्ति किसी राजनीतिक पद पर नहीं हो सकती। इसके बाद कार्की के नाम पर विचार नहीं हुआ। एक समूह बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर अड़ा था, पर उन्होंने मना कर दिया और चुनाव के जरिए सरकार में आने की इच्छा जताई। इसके बाद तीसरे समूह ने बिजली बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष कुलमान घीसिंग का नाम प्रस्तावित किया, पर असहमति जता दी गई। इसके बाद वहाँ उपस्थित दो समूह नेतृत्वकर्ताओं के नाम पर भिड़ गए। इस

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.23

पर सेना ने स्थिति संभाली और मुख्यालय परिसर खाली करा लिया। इसी बीच सेना प्रमुख अशोक राज सिगरेल के 12 से 20 सितंबर तक चीन दौरे से संबंधित प्रोटोकॉल वायरल हो गया। यह दौरा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 12 वें बीजिंग ज्यांगसान फोरम में भाग लेने से संबंधित था। पत्र वायरल होने के बाद सेना प्रमुख का चीन का दौरा रद्द होने की खबर आ गई। इसके अलावा जेन–जी प्रतिनिधियों ने प्रेस से बात करते हुए कहा, यह पूरी तरह से नागरिक आंदोलन है, इसलिए इसमें राजनीति करने की कोशिश न करे। हमारे सामने राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता की रक्षा और आत्मसम्मान बनाए रखने की चुनौती है।' साथ ही कहा कि संसद को भंग कर देनी चाहिए और लोगों की भावना के अनुसार संविधान में बड़े संशोधन किए जाने चाहिए। उनका संविधान खत्म करने का कोई इरादा नहीं है और न ही देश का नेतृत्व संभालने का इरादा है, वे सिर्फ प्रहरी बने रहना चाहते है।[6] अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर जेन–जी समूहों में मतभेद व सेना मुख्यालय के सामने भिड़ंकत के बाद स्थिति अनियंत्रित होती दिख रही थी। 12 सितंबर 2025 को सुबह से आंदोलन तेज करने की जेन–जी की चेतावनी से स्थिति गंभीर हो गई थी। तब नेपाल के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल ने 'संविधान के दायरे में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने का आह्वान किया। घिमरे और दहल के बीच बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया, कानून के शासन और संविधानवाद की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से प्रदर्शनकारीयों की मांगों पर ध्यान देने और एक मजबूत, समृद्ध लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध होने का भी आग्रह किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिगड़ोल, कानूनविद ओमप्रकाश आर्याल के साथ जेन–जी समूहों की बैठक हुई एवं सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। कई संविधानविदों ने सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर गैर–संसदीय व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यदि संसद भंग करने की जरूरत पड़ी तो उससे पूर्व बैठक बुलाकर संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिक सरकार के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

अंततः जेन–जी आंदोलन में पाँच दिनों तक सुलगने वाला नेपाल का संविधानिक संकट समाप्त हो गया। जब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिगड़ेल, कानूनविद ओमप्रकाश आर्याल और जेन–जी के प्रतिनिधियों की सात घंटे तक चली बैठक के बाद सुशील कार्की को 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सपथ दिलाई गई। नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने वाली 73 वर्षीय कार्की अब देश की पहली महिला पीएम भी बन गई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने शीतल निवास में कार्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार का कार्यकाल छह माह होगा, और उसे मार्च 2026 तक संसदीय चुनाव करा लेने होंगे। शपथ ग्रहण के बाद कार्की ने संसद भंग करने की सिफारिस की, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया और उसकी औपचारिकता पूरी की। इस घटनाक्रम पर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) संसद भंग करने के फैसले पर असहमति जताई। पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2025 को केन्द्रीय पदाधिकारी समिति की आपात बैठक में नेपाल की मौजूदा हालत की समीक्षा की गई। पार्टी अध्यक्ष अर्नि सापकोटा ने एक बयान में कहा, संविधान व्यवस्था के विपरीत संसद भंग करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन माओवदी केंद्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के पक्ष में खड़ा

रहेगा।[7] सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में हालात सामान्य होने लगे। इस बीच राष्ट्रपति पौडेल के कार्यालय ने घोषणा कि नेपाल में संसदीय चुनाव 5 मार्च 2026 को कराए जाएंगे।

भारत के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। नेपाल भारत का करीबी मित्र है। मुझे उम्मीद है कि अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेंगी। कार्की नेपाल की पहली पीएम है, जोकि महिलाओं के सशक्तीकरण का एक अच्छा उदाहरण है।' इसके अलावा नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत जयंत प्रसाद ने कहा है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति महत्वपूर्ण समय पर हुई है। वह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नेता है, जो देश को स्थिरता प्रदान कर सकती है और चुनाव सुनिश्चित कर सकती है। प्रसाद ने कहा कि आंदोलन अगर लंबा खींचता तो नेपाल में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थितियाँ बनने का खतरा था। उन्होंने कहा कि 2013 में भी नेपाल में ऐसा हो चुका था और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने ही सत्ता संभाली थी और देश में सफल चुनाव कराए थे। नेपाल में नेतृत्व परिवर्तन से भारत को राहत तो मिली, लेकिन भारत विरोधी नाइरेटिव को तेजी से बदलने की जरूरत भी है। भारत के विभिन्न अधिकारियों ने कहा है कि देश में कूटनीतिक बदलाव पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि ओली के मुकाबले कार्की से तालमेल बिठाना आसान होगा। ओली को चीन के ज्यादा करीब माना जाता था, जिसकी वजह से वहाँ हाल के वर्षों में चीन का दखल भी बढ़ गया था। इसके अलावा नेपाल में अगर आंदोलन लंबा खींचता तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इसका फायदा भारत के साथ खुली सीमा के रास्ते घुसपैठ कर सकती थी। आईएसआई पहले कई मौकों पर नेपाल से सटे सीमा के माध्यम से फायदा उठा चुकी है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसीयों के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो सकता था।[8]

नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन से चीन ने भी सुशीला कार्की को नेपाल के अंतिम प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और दोनों पड़ोसी देशों के बीच पुरानी मित्रता पर जोर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चीन, मैडम सुशील कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता है। चीन और नेपाल के बीच पुरानी मित्रता है। चीन, हमेशा की तरह नेपाल के लोगों के फैसला का सम्मान करता है। प्रवक्ता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों को बढ़ावा देने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान–प्रदान, सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए नेपाल के साथ काम करने को तैयार है।[9]

नेपाल में जेन–जी समूह के द्वारा नेपाल में सरकार के विरोध में व व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से भारत–नेपाल सुदृढ़ होंगे। 5 मार्च 2026 में नेपाल में होने वाले चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा कि नेपाल में किस दल की सरकार बनती है, भारत समर्थित राजनीतिक दल या नेतृत्व सत्ता संभालेगी या चीन के तरफ झुकाव रखने वाली माओवादी दल। भारत ने हमेशा से नेपाल में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, संबंध सुदृढ़ करने पर बल दिया है। यद्यपि नेपाल के तरफ कोई भारत विरोधी कदम न उठाया गया हो। नेपाल में माओवदियों का शासन में आने के उपरांत भारत विरोधी आवाजें उठने के साथ चीन के तरफ झुकाव ज्यादा देखा गया है। जिससे संबंधों में

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.23

उतार–चढ़ाव भी कुछ वर्षों देखा गया है। लेकिन भारत ने हमेशा संयम से समाधान निकालकर संबंधों को मजबूत कर नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से प्रयासरत है।

संदर्भ

1. शुक्ल, कृष्णानंदः भारत–नेपाल संबंध, अंकित पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011 पृ0सं0–23–28।
2. https://www.indembkathmandu.gov.in/aboutindianepalrelations
3. दैनिक जागरण, 9 सितंबर, 2025
4. दैनिक जागरण, 10 सितंबर, 2025
5. दैनिक जागरण, 11 सितंबर, 2025
6. दैनिक जागरण, 12 सितंबर, 2025
7. दैनिक जागरण, 13 सितंबर, 2025
8. दैनिक जागरण, 14 सितंबर, 2025
9. जनसत्ता, 15 सितंबर, 2025